समृद्ध किसान सशक्त मध्यप्रदेश

सहकार से समृद्धि... बीज विपणन, दुग्ध समितियों से लेकर जिला सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने की पहल के साथ बदल रही है गांवों की तस्वीर

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस; प्रदेश की सभी 4,536 पैक्स संस्थाएं पूरी तरह डिजिटल

वित्तीय समावेशन में देश का अग्रणी राज्य बना मप्र

भोपाल

मध्यप्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है। प्रदेश की सभी 4,536 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) को शत-प्रतिशत डिजिटल कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक कंप्यूटरीकरण के साथ मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। इस डिजिटल क्रांति से किसान जल्द ही मोबाइल एप के जरिए अपनी समिति से जुड़ सकेंगे। वे अपने वित्तीय ट्रांजेक्शन और ऋण संबंधी कार्य घर बैठे ही आसानी से कर पाएंगे।

कमजोर सहकारी बैंकों के लिए विशेष कार्ययोजना

मध्यप्रदेश सरकार ने कमजोर जिला सहकारी बैंकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 साल का लक्ष्य तय किया है। इस दिशा में तेजी से काम करते हुए पिछले ढाई साल में 18 कमजोर जिला सहकारी बैंकों में से 6 बैंकों की माली हालत में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए जा चुके हैं।

सहकारिता विभाग की बैठक में सीएम डॉ. मोहन यादव।

2 वर्षों में 14 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का विपणन

बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) और राज्य के सहकारी बीज संघ के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इस साझेदारी से अब तक 17 करोड़ रुपये का व्यावसायिक टर्नओवर मिल चुका है। इसके साथ ही 844 पैक्स संस्थाएं इसकी सदस्य बन चुकी हैं। इस व्यवस्था के तहत पिछले 2 वर्षों में 14 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का रिकॉर्ड उत्पादन और देशव्यापी विपणन किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 1,102 नई दुग्ध समितियों का गठन

सहकारिता का दायरा बढ़ाते हुए ग्रामीण इलाकों में 1,102 नई दुग्ध सहकारी समितियां बनाई गई हैं। अब प्रदेश में कुल दुग्ध समितियों की संख्या बढ़कर 5,562 हो गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 76 हजार नए दुग्ध उत्पादक सदस्यों के बचत खाते सीधे जिला सहकारी बैंकों में खोले गए हैं।

डिजिटल सहकारिता क्रांति

- **घर बैठे बैंकिंग:** सभी 4,536 पैक्स के डिजिटल होने से किसानों को बिना चक्कर काटे ऋण और खाद-बीज की पारदर्शी सुविधाएं सीधे मिलेंगी।
- **प्रमाणित बीज की आसान पहुंच:** 14 लाख क्विंटल रिकॉर्ड प्रमाणित बीजों के विपणन से किसानों को उन्नत और उच्च गुणवत्ता वाले बीज समय पर मिल रहे हैं।
- **सुदृढ़ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: 6** जिला सहकारी बैंकों की आर्थिक स्थिति सुधरने से किसानों को स्थानीय स्तर पर बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिल रही हैं।
- **दुग्ध उत्पादकों को संबल: 76** हजार नए सदस्यों के बैंक खाते खुलने से दूध की बिक्री का पैसा बिना किसी देरी के सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है।

प्रतिदिन दुग्ध संकलन 10 से बढ़ाकर 50 लाख लीटर करने का रोडमैप तैयार

देश की मिल्क कैपिटल बनेगा एमपी

एनडीडीबी के साथ ऐतिहासिक अनुबंध, दुग्ध संघों के खरीदी मूल्य में ₹8.50 प्रति ली. तक की रिकॉर्ड बढ़ोतरी

दुग्ध संकलन वाले गांवों की संख्या अगले 5 वर्ष में 9 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करने की तैयारी में सरकार

भोपाल

मध्यप्रदेश को देश की अग्रणी 'मिल्क कैपिटल' के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सांची ब्रांड को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ ऐतिहासिक अनुबंध किया है। इसके तहत दैनिक दुग्ध संकलन क्षमता बढ़ाकर 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का रोडमैप तैयार किया गया है। पशुपालकों को उनके परिश्रम का सही मूल्य दिलाने के लिए दुग्ध संघों द्वारा दूध की खरीदी दरों में रिकॉर्ड 2.50 से लेकर 8.50 रुपये प्रति लीटर तक की भारी बढ़ोतरी की गई है। इसके फलस्वरूप दुग्ध संघों ने उत्पादक किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक राशि का सीधा भुगतान किया है। वर्तमान में प्रदेश में प्रतिदिन 9.67 लाख किलोग्राम औसत दुग्ध संकलन की ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हो चुकी है। अगले 5 वर्षों के भीतर दूध संकलन वाले गांवों की संख्या को 9 हजार से बढ़ाकर 26 हजार किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के कम से कम 50 प्रतिशत गांवों में प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियां बनाई जाएंगी।

बाजार की चिंता खत्म, दैनिक आय में बढ़ोतरी के साथ स्वरोजगार पर जोर

एनडीडीबी से करार के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का स्वागत करते सीएम।

- **सुनिश्चित खरीदी :** अगले 5 वर्षों में दायरा 9 हजार से बढ़कर 26 हजार गांव होने से पशुपालकों को दूध बेचने के लिए अपने गांव में ही पक्का बाजार मिल जाएगा।
- **सीधे खाते में ज्यादा लाभ:** खरीदी दरों में ₹8.50 प्रति लीटर तक की वृद्धि और कुल भुगतान में 15% की बढ़ोतरी से ग्रामीण परिवारों की दैनिक नकदी आय बढ़ी है।
- **कमर्शियल डेयरी को संबल:** 42 लाख रुपये तक के ऋण पर 33% तक की भारी सरकारी सब्सिडी से युवाओं के लिए डेयरी क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करना आसान हुआ है।
- **नस्ल सुधार से उत्पादन:** हिरण्यगर्भा अभियान के तहत उन्नत पशु नस्ल तैयार होने से प्रति पशु दुग्ध उत्पादन क्षमता में आने वाले समय में भारी वृद्धि होगी।

वृंदावन ग्राम योजना व डॉ. अम्बेडकर कामधेनु योजना के साथ दुग्ध उत्पादकों को सौगात

ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को लाभकारी बनाने के लिए हर विकासखंड के एक गांव को आदर्श वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। डॉ. अम्बेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की नई कमर्शियल डेयरी इकाई लगाने के लिए ₹42 लाख तक की ऋण सहायता दी जा रही है, जिसमें 25% से लेकर 33% तक की भारी सब्सिडी का प्रावधान है। इसके अलावा 10 से ज्यादा गाय पालने पर सरकार द्वारा विशेष अनुदान दिया जा रहा है।

ग्वालियर में बायोगैस सीएनजी प्लांट स्थापित, हिरण्यगर्भा अभियान से होगा नस्ल सुधार

शुधन कल्याण के लिए ग्वालियर की आदर्श गौ-शाला में देश के पहले 100 टन क्षमता वाले बायोगैस आधारित सीएनजी प्लांट की सफल स्थापना की जा चुकी है। चिकित्सा सुविधाओं को सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए ग्वालियर में आधुनिक 'पशु केयर एंड वेलनेस सेंटर' तथा डबरा में नया हाईटेक पशु चिकित्सालय स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही पशुओं के नस्ल सुधार के लिए पूरे प्रदेश में "हिरण्यगर्भा अभियान" का प्रभावी संचालन किया जा रहा है।

नीली क्रांतिः 'कुवैत की अंतरराष्ट्रीय मत्स्य कंपनी के साथ 7,430 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक एग्रीमेंट

मत्स्य पालन में वैश्विक छलांग, नई नीति होगा 9,000 करोड़ का निवेश

प्रदेश से 6,000 करोड़ के मत्स्य निर्यात का वार्षिक निर्यात का लक्ष्य

भोपाल

मध्यप्रदेश में नीली क्रांति को रफ्तार देने और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत मत्स्य उद्योग नीति-2026 लागू की गई है। इस नई नीति के दूरगामी प्रभावों के चलते मत्स्य पालन क्षेत्र में 9,000 रुपये करोड़ से अधिक के भारी औद्योगिक निवेश के प्रस्ताव जमीन पर उतर रहे हैं। राज्य के पास वर्तमान में उपलब्ध 4 लाख 40 हजार हेक्टेयर के विशाल जलक्षेत्र का अब पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया जा रहा है, जिससे एमपी ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान बनाई है। नई मत्स्य नीति के तहत एमपी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है। कुवैत की एक प्रतिष्ठित वैश्विक कंपनी ने राज्य सरकार के साथ 7,430 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक व्यापारिक समझौता किया है। इस समझौते के माध्यम से प्रदेश से सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगभग 6,000 करोड़ रुपये के उच्च गुणवत्ता वाले मत्स्य निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 35 हजार से अधिक नए रोजगार के अवसर तैयार होंगे।

: मत्स्य पालन को आधुनिक और वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए काम जारी है। इसके तहत राज्य में केज कल्चर, फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्मार्ट फिश पार्लर और कोल्ड चैन इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही धान उत्पादक किसानों को अपने खेतों में मछली पालन करने के लिए विशेष वित्तीय और तकनीकी मदद दी जा रही है।

मछुआरों को यह फायदे मिलेंगे

- **रोजगार के नए अवसर:** कुवैत की कंपनी के साथ हुए समझौते से प्रदेश में 35 हजार से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए मौके मिलेंगे।
- **दोहरी आय का साधन:** धान की खेती के साथ मछली पालन जोड़ने से किसानों को अतिरिक्त लागत लगाए बिना कमाई का दूसरा पक्का जरिया मिल रहा है।
- **आसान वित्तीय मदद:** मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पारंपरिक मत्स्य पालकों को बेहद कम ब्याज दर पर तुरंत लोन की सुविधा मिल रही है।
- **नए उद्योगों से मुनाफा:** हर जिले में हैचरी और मोती पालन शुरू होने से स्थानीय युवाओं को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण और स्वरोजगार का लाभ मिलेगा।

आधुनिक हैचरी और ब्लू टूरिज्म को बढ़ावा

प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक आधुनिक और उन्नत मत्स्य हैचरी विकसित की जा रही है। इसके अलावा एक्वापोनिक्स, मोती पालन, बतख पालन और जलाशयों के आसपास ब्लू टूरिज्म मॉडल्स को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण में भी प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है।

वन विज्ञान केंद्रों के लिए 48 करोड़ स्वीकृत

किसानों को मिलेगा औषधीय व व्यावसायिक खेती का प्रशिक्षण

भोपाल

मध्यप्रदेश में किसानों को व्यावसायिक और औषधीय खेती का प्रशिक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा नीतिगत ढांचा तैयार किया है। इसके तहत वनों के पास रहने वाले कृषकों को कृषि-वानिकी की आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाएगा। सरकार ने वर्ष 2025-26 से 2029-30 की अवधि के भीतर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 6 नए अत्याधुनिक वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 48 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ये केंद्र किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ कीमती औषधीय पौधों और व्यावसायिक वन वृक्षों को लगाने की वैज्ञानिक पद्धतियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इससे पर्यावरण संरक्षण में सुधार होने के साथ-साथ ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और किसानों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित होगी।

तकनीक बनी वरदान..कीटों से शत-प्रतिशत बचाव, ऑफ-सीजन में भी बंपर उत्पादन

कम पानी और शून्य बजट में फसलों की सुरक्षा; तेजी से बढ़ रहा संरक्षित खेती का दायरा, पॉलीहाउस और शेडनेट बने वरदान

टपक सिंचाई (ड्रिप) और मल्चिंग तकनीक से लागत में आधी कमी

भोपाल

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक खेती के साथ-साथ अब संरक्षित खेती को एक नई और अत्यधिक मुनाफे वाली कृषि पद्धति के रूप में तेज़ी से अपनाया जा रहा है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में प्रदेश के हजारों किसान अब खुले खेतों की पारंपरिक कृषि को छोड़कर आधुनिक पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस की तरफ रुख कर रहे हैं।

इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके अंतर्गत फसलों को अत्यधिक तेज धूप, ओलावृष्टि, पाला और

हानिकारक कीटों के आक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे फसलों का उत्पादन 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। इस पद्धति के तहत विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास मिशन और पीएम सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों को 40% से 50% तक का भारी शासकीय अनुदान प्रदान किया जा रहा है, जिससे लागत बेहद कम हो जाती है।

ड्रिप इरीगेशन (टपक सिंचाई) और प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाता है। ड्रिप तकनीक से पौधों की जड़ों तक सीधे बूंद-बूंद पानी और आवश्यक लिक्विड फर्टिलाइजर पहुंचाया जाता है, जिससे पानी की 70% तक बचत होती है और खाद का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता। वहीं, मल्चिंग पेपर बिछाने से खेतों में खरपतवार पूरी तरह समाप्त हो जाती है और मजदूरी की लागत में भारी कमी आती है। मालवा और निमाड़ अंचल के जिलों में इस पद्धति से खीरा-ककड़ी, शिमला मिर्च, तरबूज और गुलाब जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लिया जा रहा है, जो कम समय में किसानों को लखपति बनाने वाली सर्वश्रेष्ठ पद्धति साबित हो रही है।

उद्यानिकी नवाचार, कृषि नीति एवं इंफ्रास्ट्रक्चर

1. **₹20.00 करोड़** — BARC बॉम्बे के सहयोग से भोपाल में 'विकिरण तकनीकी इकाई' की स्थापना
2. **₹1.25 करोड़** — RRCAT के सहयोग से इंदौर में अत्याधुनिक 'शीतल वाहक संयंत्र' परियोजना
3. **₹11.34 करोड़** — सागर (झिला) व देवास (कन्नौद) में संकर सब्जी बीजोत्पादन क्लस्टर
4. **₹2.5 करोड़** — मालवा व चंबल के 12 प्रमुख जिलों में 'पोटेटो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग'
5. **10 नए जिले** — जबलपुर, रीवा, कटनी आदि 10 नए जिलों में मखाना खेती का सफल प्रसार
6. **₹505 करोड़** — गौसंवर्धन बोर्ड का बजटीय कोष गौशालाओं को चारा-भूसा अनुदान हेतु
7. **2,056+ गौशालाएं** — प्रदेश में सरकारी संरक्षण में संचालित, जहां 3.98 लाख गौ-वंश का पालन
8. **4 'आदर्श' जिले** — आगर मालवा, इंदौर, ग्वालियर व उज्जैन में सर्वसुविधायुक्त आदर्श गौशालाएं

करुणा और सेवा का नया अध्याय... पशुपालन विभाग को अब गौपालन का नाम, आर्थिक स्वावलंबन से सुविधाओं तक का खाका तैयार

प्रति गौ-वंश दैनिक आहार भत्ता राशि अब दोगुना; प्रदेश की 2,000 से ज्यादा गौशालाओं में पल रहे 3.98 लाख से अधिक गौ-वंश को मिला आर्थिक संबल

भोपाल

भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन की धुरी माने जाने वाले गौ-वंश के संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने करुणा और संवेदनशीलता से भरा एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पशुपालन विभाग का नाम अब आधिकारिक रूप से 'गौपालन विभाग' कर दिया गया है। गौ-वंश के बेहतर और पौष्टिक आहार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रति गौ-वंश मिलने वाली 20 रुपये की दैनिक आहार राशि को सीधे दोगुना करके 40 रुपये कर दिया है। इस योजना को निर्बाध रूप से चलाने के लिए प्रदेश के गौसंवर्धन बोर्ड को 505 करोड़ रुपये के भारी बजटीय कोष का विशेष प्रावधान किया गया है।

चारा-भूसा अनुदान के लिए 505 करोड़ रुपये का विशेष बजटीय कोष

वर्तमान में सरकार के सहयोग से प्रदेश में 2,056 से अधिक गौ-शालाओं का सफल संचालन हो रहा है। इन गौशालाओं में 3 लाख 98 हजार से अधिक गौ-वंश का पूरी संवेदनशीलता के साथ पालन-पोषण किया जा रहा है। वहीं, 4 जिलों-आगर मालवा, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन में आधुनिक सुविधाओं से युक्त आदर्श गौशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि भोपाल, जबलपुर और सागर में इनका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

पंचगव्य उत्पादों से आत्मनिर्भर बनेंगी गौशालाएं: सरकार ने स्वावलंबी गौ-शालाओं की स्थापना नीति-2025 को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत गौशालाओं के पंचगव्य उत्पादों, जैविक खाद, गोमूत्र अर्क और प्राकृतिक कीटनाशकों की बिक्री के लिए एक आधुनिक मार्केटिंग नेटवर्क तैयार किया जा रहा है।

हाइड्रोलिक व्हीकल से मिलेगा नया जीवन: सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त या बीमार होने वाली असहाय गायों के त्वरित उपचार के लिए भी एक अनूठी व्यवस्था की गई है। राज्य के प्रमुख शहरी और ग्रामीण केंद्रों पर अत्याधुनिक हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग वाहनों की तैनाती की गई है।

समृद्धि के 3 सूत्र

- **आहार राशि में 100% वृद्धि:** प्रति गाय दैनिक भत्ता ₹20 से बढ़कर ₹40 होने से अब गौशालाओं में पशुओं को अधिक पौष्टिक और पर्याप्त मात्रा में चारा-भूसा मिल सकेगा।
- **सुरक्षित परिवहन:** अत्याधुनिक हाइड्रोलिक वाहनों की तैनाती से सड़क पर घायल होने वाली असहाय गायों को बिना अतिरिक्त पीड़ा के तुरंत इलाज मिलना संभव हुआ है।
- **आत्मनिर्भरता का नया मॉडल:** स्वावलंबी नीति के तहत जैविक खाद और गोमूत्र अर्क के व्यावसायिक विपणन से गौशालाओं की दैनिक आय में सुधार होगा।

D-11085/26